सितम्बर , 2023, वर्ष : 44 अंक : 09 www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

निर्वासित तिब्बती सरकार के सिक्योंग पेंपा छेरिंग।

मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

सितम्बर, 2023, वर्ष : 44 अंक : 09

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परम पवन दलाई लामा।

प्रधान संपादक
जमयंग दोरजी, थुप्तेन रिन्ज़ीन

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
तेनजिन जोरदेन

वितरण प्रबंधक
छोन्यी छरिंग, ताशी देकि

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

समाचार -

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिकशुभकामनाएं:परम पावन दलाई लामा 1
- तिब्बती लोकतंत्र दिवस की तिरसठवीं वर्षगांठ पर कशाग का वक्तव्य 2
- यूरोपीय संघ के सांसदों ने सीटीए की लोकतांत्रिक प्रणालीको समझने के लिए सिक्योंग पेन्पा छेरिंग से मुलाकात की 3
- चीन के 'ऑर्डर नंबर १९'से तिब्बत में उसका चल रहा निरंतर धार्मिक दमन और बढ़ा 4
- तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कलास से मुलाकात की, ओजीपी ग्लोबल समिट २०२३ में भाग लिया 5
- स्वीडिश संसदीय शिष्टमंडल ने तिब्बतियों के साथ एकजुटता व्यक्त की 6
- ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी ने तिब्बत में अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया 7
- ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर जेनेट राइस ने परमपावन दलाई लामा के पुनर्जन्म और तिब्बत में मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर चिंता जताई 8
- डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग ने आईपीएसी के प्राग शिखर सम्मेलन में भाग लिया 9
- यूरोपीय बौद्ध संघ ने चीनी सरकार से तिब्बती बौद्ध मामलों में हस्तक्षेप न करने का आह्वान किया 10

समाचार -

- सीजीटीसी-आई के प्रतिनिधिमंडल ने गंगटोक में ६३वें तिब्बती लोकतंत्र दिवस में भाग लिया, उत्तर बंगाल और सिक्किम का दौरा किया 11
- ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत में '२१वीं सदी में तिब्बत को जानें' एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित 12
- 'विदेश नीति से परे तिब्बत' विषय पर सेमिनार में विशेषज्ञों ने तिब्बत की भयावह स्थिति पर प्रकाश डाला 13
- सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग ने कोलकाता के संस्कृत कॉलेज और विश्वविद्यालय में तिब्बत पर सेमिनार और यात्रा प्रदर्शनी आयोजित किया 14
- मानवाधिकार डेस्क और तिब्बत संग्रहालय ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम के विश्वविद्यालयों में भाषण यात्रा और प्रदर्शनी पूरी की 15
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधिमंडल निर्वासित तिब्बती संसद पहुंचा 16
- इंडियन एसोसिएशन ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉरेस्पोंडेंट्स (आईएएफएसी) के प्रतिनिधिमंडल ने धर्मशाला में 17

मुद्रक एवं प्रकाशक
जमयांग दोरजी द्वारा
नोरबू ग्राफ़िक्स , 1/6, बेसमेंट
विक्रम विहार , लाजपत नगर
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट
www.indiatibet.net
Email:
indiatibet7@gmail.com

◆ तिब्बत के लोकतंत्रीकरण से चिंतित है साम्यवादी चीन

नई दिल्ली में सम्पन्न जी-20 की षिखर वार्ता (9-10 सिंतबर, 2023) में विस्तारवादी चीनी राष्ट्रपति शी जिंपिंग की अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि चीन अंतरराष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ता जा रहा है। वे उपस्थित होकर भी जी-20 के सर्वसम्मत घोषणापत्र को पारित होने से रोक नहीं पाते। उन्हें इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरीडोर (प्डम्ब्) परियोजना को स्वीकारना पड़ता। इस परियोजना के कारण चीन की वन बेल्ट वन रोड (व्ठव्त्) परियोजना संकटग्रस्त हो गई है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना चीन की एक विस्तारवादी परियोजना है जबकि जी-20 की इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरीडोर परियोजना से विष्वस्तर पर परस्पर वाणिज्य-व्यापार-आवागमन तथा संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिंपिंग को भारत में तिब्बती विरोध प्रदर्षन का भी सामना करना पड़ता।

शी जिंपिंग को अपनी भारत विरोधी गतिविधियों के कारण भी शर्मीन्दगी झेलनी पड़ती। तिब्बत को चीन की हथेली और भारत में लद्दाख, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेष को तथा भूटान एवं नेपाल को उसकी अंगुलियाँ समझने वाले शी जिंपिंग को मुँहतोड़ जवाब मिलने का पूरा विष्वास था।

स्वतंत्र तिब्बत पर सन् 1959 में अवैध नियन्त्रण स्थापित कर चुका चीन तथाकथित पाँच अंगुलियों पर अवैध नियन्त्रण के लिये साजिषपूर्ण साम्राज्यवादी नीति पर चल रहा है। अच्छी बात है कि वर्तमान भारत सरकार से हर मोर्चे पर चीन को कड़ी चुनौती मिल रही है। नई दिल्ली में शी जिंपिंग की अनुपस्थिति का महत्वपूर्ण कारण भारत की बढ़ती राष्ट्रीय शक्ति है। भारतीय राष्ट्रीय हितों की रक्षा तत्परता से हो रही है।

चीन से भारतीय राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के सन्दर्भ में निर्वासित तिब्बत सरकार की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु परमपावन दलाई लामा के समान निर्वासित तिब्बत सरकार भी भारत-चीन संबंधों के विष्वसनीय एवं सुदृढ़ होने का पक्षधर है। इन दोनों के मतानुसार पहले भारत एवं चीन के बीच स्वतंत्र तिब्बत एक मध्यस्थ राज्य (बफर स्टेट) था। उस समय भारत एवं चीन की सीमा नहीं मिलती थी। तब भारत एवं चीन के संबंध बहुत अच्छे थे। तिब्बत पर अवैध चीनी नियंत्रण के कारण भारत-तिब्बत सीमा की जगह भारत-चीन सीमा पैदा हो गई। ये चाहते है कि चीन की तुलना में भारत अपनी राष्ट्रीय शक्ति में लगातार विस्तार करे। शक्तिषाली भारत ही लोकतंत्र विरोधी चीन की अमानवीय एवं अवैध उपनिवेषवादी नीति को रोकने में मददगार हो सकता है।

चीन की बौखलाहट का महत्वपूर्ण कारण है-भारत का शक्तिषाली होना तथा तिब्बती समाज का लोकतंत्रीकरण। परमपावन दलाई लामा तिब्बत के राजप्रमुख और धर्मप्रमुख थे। वर्ष 2001 में पहली बार तिब्बती समाज में वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव हुए। तिब्बतियों ने लोकतांत्रिक तरीके से मतदान द्वारा अपनी निर्वाचित सरकार का गठन किया। यह सरकार चूँकि निर्वासित

तिब्बतियों द्वारा हिमाचल प्रदेष की धर्मषाला में संचालित होती है इसीलिये इस निर्वाचित तिब्बत सरकार को निर्वासित तिब्बत सरकार कहा जाता है। दलाई लामा ने वर्ष 2011 में अपने सारे राजनीतिक अधिकार इसी सरकार को सौंप दिये। अब उनके पास सिर्फ धार्मिक अधिकार हैं।

तिब्बती समुदाय का लोकतंत्रीकरण दलाई लामा की प्रेरणा-प्रोत्साहन-प्रयास का परिणाम है। इससे अहिंसक तिब्बती संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय सहयोग-समर्थन बढ़ता जा रहा है। तिब्बत की आंतरिक दुर्दषा के विरोध में समस्त लोकतांत्रिक शक्तियाँ एकजुट हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा देश तिब्बत में जारी मानवाधिकार हनन, प्राकृतिक संसाधनों के विनाष तथा पर्यावरण-प्रदूषण रोकने हेतु चीन पर दबाव बढ़ा रहे हैं। तिब्बतियों के धार्मिक मामलों में चीनी हस्तक्षेप का विष्वव्यापी विरोध इसी का उदाहरण है। अमेरिका सहित कई देषों द्वारा तिब्बत एवं तिब्बतियों के चीनीकरण के विरूद्ध चीन को गंभीर परिणाम की चेतावनी दी गई है।

चीन नहीं चाहता कि तिब्बत में लोकतंत्र मजबूत हो। वह स्वयं एक धर्मविरोधी और लोकतंत्रविरोधी साम्यवादी देष है। तिब्बत की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। तिब्बती और तिब्बत समर्थक सर्वाधिक चिंतित इसी से हैं कि तिब्बती पहचान मिटाने की चीनी नीति लगातार जारी है। इसीलिये वे तिब्बत की "पूर्ण स्वतंत्रता" के स्थान पर "वास्तविक स्वायत्तता" की मांग कर रहे हैं। "वास्तविक स्वायत्तता" मिलने से तिब्बती पहचान की सुरक्षा हो जायेगी। चीनी संविधान तथा राष्ट्रीयता संबंधी कानून के अनुरूप चीन अपने पास प्रतिरक्षा तथा विदेष विभाग रखे। कृषि एवं षिक्षा सहित अन्य विषय तिब्बतियों को सौंपे जायें। इससे चीनी संप्रभुता के साथ तिब्बती स्वषासन के सैद्धांतिक एवं संवैधानिक विचार का संरक्षण एक साथ हो जायेगा। अभी स्वायत्तता के नाम पर चीन ने तिब्बत के भौगोलिक क्षेत्र को बुरी तरह विकृत कर रखा है।

विष्व समुदाय तिब्बती लोकतंत्रीकरण का समर्थक है जबकि चीन के अनुसार इसके प्रेरणास्रोत दलाई लामा आंतककारी-विघटनकारी हैं। चीन अपनी यह दुर्भावना छोड़े तथा दलाई लामा एवं निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बंद पड़ी वार्ता पुनः प्रारम्भ करे। तिब्बत समस्या का शीघ्र समाधान विष्वषांति, विषेषकर भारतीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि एवं स्वाभिमान की दृष्टि से बहुत आवष्यक है। विस्तारवादी हठधर्मिता चीन को छोड़नी होगी।

चीनी हठधर्मिता का ही परिणाम है कि अपने सभी पड़ोसी देषों के साथ चीन के संबंध शत्रुतापूर्ण हैं। सभी सीमावर्ती देषों को चीनी विस्तारवाद का षिकार होना पड़ा है। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र संकटग्रस्त है। हिमालय की सुरक्षा तथा इस क्षेत्र के विकास के लिये चीन की भोगवादी नीति पर अंकुष लगाना होगा। इससे कई ग्लेसियर सूखने-सिकुड़ने लगे हैं। कई वन्य जीव लुप्त हो चुके। उसके इस अस्वीकार्य आचार-विचार-व्यवहार पर अंकुष लगाने के लिये विष्व स्तरीय एकजुटता स्वागतयोग्य है।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)

मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

◆ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिकशुभकामनाएं:परम पावन दलाई लामा

dalailama.com, १७ सितंबर,२०२३

थेकचेन चोएलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत।परम पावन दलाई लामा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्तरवें जन्मदिन (१७ सितंबर) के अवसर पर पत्र लिखकर उन्हें हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं।

परम पावन ने लिखा, 'मैं आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको भारत द्वाराजी-२०शिखर सम्मेलन की सफल अध्यक्षता की बधाई देता हूं, जिसका समापन 'वसुधैव कुटुंबकम-एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'की थीम पर हुआ है। यह एक ऐसा विषय है, जिसके साथ मेराअटूट जुड़ाव है। मैं मानवता की एकता में दृढ़ता से विश्वास करता हूं और अवसर मिलते ही इसके महत्व को प्रसारित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता हूं।'

'भारत में सबसे लंबे समय तक रहते हुए मुझे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का कद बढ़ता देखकर बड़ा सौभाग्य और संतुष्टि मिली है। इसका साक्ष्य जी-२० शिखर सम्मेलन जैसे आयोजनों में भी दिखता है। इस बैठक से यह उजागर करने का मौका मिला कि हमारी दुनियापरस्पर निर्भरता पर आधारित है।'

उन्होंने कहा,'भारत की अहिंसा और करुणा की परंपराएं१००० वर्ष से अधिक पुरानी हैं। इस पृथ्वी पर सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में अंतर-धार्मिक सद्भाव की एक लंबी परंपरा रही है और भारत दुनिया के सामने इसके माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताएं इसके विकासको और बढ़ाती है।'

तिब्बती लोगों की ओर सेमैं एक बार फिर पिछले ६४ वर्षों में अपनेआतिथ्य और उदारतापूर्वक मिले सहायता के लिए भारत की सरकार और भारतीयलोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

परम पावन ने अपने पत्र का समापन प्रार्थनाओं के साथ किया और कामना की कि प्रधानमंत्री 'इस महान देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने और अधिक करुणा, शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण में योगदान देने के लिए स्वस्थ रहें और अपनी सफलता की गाथा लिखना जारी रखें।'

◆ तिब्बती लोकतंत्र दिवस की तिरसठवीं वर्षगांठ पर कशाग का वक्तव्य

tibet.net, ०२ सितंबर,२०२३

आज हम ऐतिहासिक तिब्बती लोकतंत्र दिवस की तिरसठवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर कशाग (तिब्बत की निर्वासित सरकार का मंत्रिपरिषद) तिब्बत के अंदर और बाहर दोनों जगह रहनेवाले तिब्बतियों की ओर से तिब्बती राजनीति कव्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए परम पावन महान चौदहवें दलाई लामा को गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस अवसर पर कशाग अपने विशिष्ट अतिथियोंको भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता है। हमारे अतिथिगण हैं- स्वीडिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल मॉडरेट पार्टी के माननीय सांसद मार्गरेटा एलिज़ाबेथ सीडरफेल्ट, जोहाना हॉर्नबर्गर, मैरी चार्लोट निकोलसन, मारिया विक्टोरिया स्टॉकहॉस, एलेक्जेंड्रा एंस्ट्रेल, एन-सोफी लिफवेनहेज, जॉन ईवेनरहॉल, स्वीडेन डेमोक्रेट्स पार्टीके सांसद माननीय रिचर्ड जोहान्स जोम्शॉफ़ और ब्योर्न सॉडर, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी से सांसद माननीय गुडरून मार्गरेटा ब्रुनेगार्ड,ग्रीन पार्टी से सांसद माननीय जैनीन सोफिया अल्म एरिक्सन और स्वीडिश-तिब्बतकमेटी के माननीय श्री कार्ल मैटियास और सुश्री क्रिस्टीना इवा मारिया ब्योर्नरस्टेड। हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सीटीए के डोनर कांफ्रेंस (दानदाता सम्मेलन) के प्रतिनिधियों का भी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। इस अवसर परहम तिब्बत के भीतर और बाहर रहनेवाले सभी तिब्बतियों के साथ-साथ दुनिया भर में फैले तिब्बत समर्थकों और तिब्बती लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहे हैं।

कशाग द्वारा तिब्बती लोकतंत्र दिवस पर जारी पिछले दो बयानों में संक्षेप में बताया गया है कि कैसे परम पावन दलाई लामा ने वर्षों से तिब्बतियों के बीच लोकतंत्र की संस्कृति को स्थापित किया है। इन बयानों में तिब्बती प्रशासन के भीतर लोकतंत्र के तीन स्तंभों के विकास का भी सिंहाव लोकन किया गया है। आजहम तिब्बत के संवैधानिक इतिहास के क्रमिकविकास के विभिन्न चरणों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे।

जब हम अपनी कानूनी प्रणाली के इतिहास पर नजर डालते हैंतो तिब्बत के पहले राजा न्यात्री छेनपो के शासनकाल के दौरान "दो दंड और पांच दृष्टिकोण" जैसे कानूनों को सक्रिय पाते है। सम्राट सोंगछेन गम्पो के शासनकाल में दस दिव्य गुण और १६आचार संहिता लागू रहींऔर तिब्बती साम्राज्य के दौरान पांच संहिताएं और पांच कानून प्रचलित हुए। तिब्बत के विखंडन के दौर में हमारी कानूनी व्यवस्था में कुछ गिरावट देखी गई। शाक्य शासनकाल में उस समय प्रचलित मंगोलियाई कानूनों को अपनाया गया।इसके बाद फागमोद्रुपा के शासनकाल में १५ कानूनी संहिताएं, डेपा छंगपा के दौरान १६कानूनी संहिताएं और गाडेन फोडरंग के दौरान १३कानूनी संहिताएं अपनाई गईं। इस प्रकारतिब्बत ने अपने पूरे इतिहास में अपने स्वयं के राष्ट्रीय कानून, धार्मिक कानून और मानव आचार संहिताओं को नियंत्रित करने वाले कानून विकसित किए हैं।

निर्वासन में भारतआने के बाद१९६३ में परम पावन दलाई लामा ने संविधान लागू किया। इस संविधान के तहत पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे में बड़े सुधारों की शुरुआत हुईऔर लोकतांत्रिक शासन के तीनों स्तंभों के बीच नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली की शुरुआत हुई। संविधान ने करुणा, न्याय, समता, अहिंसा और पर्यावरण चेतना के मूल मूल्यों जैसे हमारे पारंपरिक लौकिक और धार्मिक कानूनी संहिताओंको बरकरार रखते हुए लोगों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की। इसके अलावाइस संविधान ने १९९१ में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सदस्यों

कीतिब्बतन पीपुल्स डिप्टीज की ११वीं सभा द्वारा निर्वासित तिब्बतियों के चार्टर को अपनाने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि को तैयार किया।

निर्वासित तिब्बतियों के चार्टर को अपनाने से पहले१९६० से १९९० तक डिप्टीज ने असेंबली ऑफ तिब्बतन पीपुल्स डिप्टीज़ (एटीपीडी) के साथ-साथ नेशनल असेंबली के स्थायी आयोग-दोनों के सदस्यों के तौर पर कार्य किया। प्रशासन और लोक कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए एटीपीडी द्वारा केंद्रीय और स्थानीय नौकरशाहोंके साथ-साथ सभी तिब्बती सेटलमेंट के प्रतिनिधियों की अर्ध-वार्षिक और वार्षिक कार्यसभाएंआयोजित की गईं। इन सभाओंने लोगों के प्रतिनिधियों को प्रशासन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर भाग लेने के लिए मंच प्रदान किया। १९७२ से १९७४ के बीच चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग और तिब्बती मुक्ति साधना के कामकाज को संचालित करने वाले नियम और कानून भी बनाए गए। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए कालोन्स, सांसदों और वरिष्ठ नौकरशाहों की उच्चस्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इन सभी गतिविधियोंने अंततः निर्वासित समुदाय के भीतर शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को साकार करने के लिए मजबूत नींव रखी।

११ से १७ मई १९९० तक धर्मशाला में तिब्बती लोगों की एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें ३६९ प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में कशाग के सदस्य, एटीपीडी के सदस्य, वरिष्ठ नौकरशाह, विभिन्न तिब्बती बौद्ध परंपराओं के प्रतिनिधि, तिब्बती गैर सरकारी संगठन, विभिन्न तिब्बती बस्तियों के प्रतिनिधि और तिब्बत से नए आए तिब्बतियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस ऐतिहासिक बैठक में परम पावन दलाई लामा ने कशाग (परमपावन दलाई लामा द्वारा नियुक्त कालोन्स) और तिब्बती पीपुल्स डिप्टीज की १०वीं सभा को भंग कर दिया। जैसा कि परम पाव न द्वारा अधिकृत किया गया था, इस विशेष बैठक ने अंतरिम कशाग के लिए तीन कलोन को निर्वाचित किया। परम पावन ने बैठक में आवश्यक लोकतांत्रिक सुधार पर चर्चा करने और इस बारे में प्रस्ताव देने का आग्रह किया। इसके बाद बैठक में १४ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इससे तिब्बती न्याय आयोग की स्थापना और निर्वासित तिब्बती संसद में तिब्बत के तीन पारंपरिक क्षेत्रों में से प्रत्येक से १० सांसदों तक,तिब्बती बौद्ध धर्म के चार संप्रदायों और मूल तिब्बती बॉन धर्म में से प्रत्येक से दो-दो सांसदोंको निर्वाचित करने की शक्ति का विस्तार हुआ। इसके साथ परम पावन दलाई लामा द्वारा नामित तीन सांसदों को इसमें स्थान दिया गय। इसके अलावापांच सदस्यीय संविधान मसौदा समिति का गठन किया गया।

संविधान सभा के रूप में अपनी भूमिका ग्रहण करते हुए इस नवगठित ११वीं तिब्बती संसद और संविधान मसौदा समिति के सदस्यों ने ३० मई १९९१ को चार्टर के मसौदे पर विचार-विमर्श किया। इसके बाद ३१ मई कोकार्यवाहक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करनियम और विनियम संसदीय प्रक्रिया और कार्य संचालन प्रणालीको अपनाया गया। ०३ से १३ जून १९९१ तक ड्राफ्ट चार्टर की सामग्री पर गहन चर्चा के बाद१४ जून १९९१ को सभी सांसदों ने निर्वासित तिब्बती चार्टर पर हस्ताक्षर किए। २८ जून १९९१ को परम पावन दलाई लामा ने चार्टर पर अपनी सहमति दे दी।

पिछले ३५ वर्षों में चार्टर में ३५ संशोधन हुए हैं। इनमें से ८५% से अधिक संशोधन तिब्बती राजनीति के तीन स्तंभों- कशाग, संसद और सर्वोच्च न्यायिक आयोग के माननीयोंकी योग्यता, चुनाव प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं। इनमें से लगभग पंद्रह१५संशोधन विशेष रूप से कशाग से संबंधित थे, जिनमें छह संशोधन २०११ के बाद किए गए। यदि हम इस संविधान के तहत मिलीं विधायी उपलब्धियों को देखेंतो चार्टर को अपनाने के दो वर्षों के भीतर ही ११कानून पारित किए गए। इनमें-संसदीय प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम और विनियमन,तिब्बती संसद की स्थायी समिति के नियम और विनियम,केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए)के प्रशासनिक नियम और विनियम,लोक सेवा आयोग के नियम और विनियम,धन जुटाने, वार्षिक बजट और वित्तीय प्रबंधन पर निर्वासित तिब्बती नियम और विनियम,क्षेत्रीय तिब्बती मुक्ति साधना समिति के नियम और विनियम,तिब्बती स्वैच्छिक अंशदान और अन्य अंशदान अधिनियम के नियम और विनियम,महालेखा परीक्षक के कार्यालय के नियम और विनियम,तिब्बती संसदीय सचिवालय के नियम और विनियम,स्टाफ क्वार्टरों और सेवानिवृत्त स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन के लिए नियम और विनियमऔर सीटीए के उत्कृष्ट कर्मचारियों को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने के लिए नियम और विनियम जैसे कानून शामिल हैं। इसी तरह १९९५ से २०१५ तक की बीस वर्षों की अवधि में१५नियम और कानून अपनाए गए। इनमें छह गणमान्य व्यक्तियों के विशेषाधिकारों और लाभों से संबंधित थे। उदाहरण के लिए, तिब्बती संसदीय आवास नियम (१९९५),तिब्बती संसद अध्यक्ष राहत ट्रस्ट कोष नियम (१९९७),निर्वासित तिब्बती चुनाव नियम (२०००),केंद्रीय तिब्बती चिकित्सा परिषद अधिनियम (२००३),न्याय आयुक्तों, सांसदों, सिक्योंग, कालोंस और तीन स्वायत्त निकायों के प्रमुखों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित छह अलग-अलग नियम और विनियम (२००४),बस्तीआवास और भूमि उपयोग विनियम (२००५),तिब्बती धार्मिक मामलों की परिषद को विनियमित करने वाला अधिनियम (२००९),स्थानीय तिब्बती सभा नियम (२०१०) के सदस्यों का दैनिक भत्ता और अन्य अधिकार, दान एकत्र करने पर नियम (२०११),तिब्बती संसद के गैर-स्थायी समिति सदस्यों के कार्यों के आधिकारिक बनाने को लेकर नियम (२०१५) शामिल हैं। हालांकि, २०१५ के बाद से कोई नया कानून पारित नहीं किया गया है।

उपरोक्तनियमों और विनियमों में से तिब्बती धार्मिक मामलों की परिषद को विनियमित करने वाला अधिनियम लागू नहीं हुआ है, जबकि कुछ अन्य कानून धीरे-धीरे अपनी प्रभावशीलता खो चुके हैं।

तिब्बती लोक सेवा आयोग के नियमों और विनियमों में सबसे अधिक २६ बार संशोधन हुए।इसके बाद निर्वासित तिब्बती चुनाव नियम में२० बारऔर कर्मचारी क्वार्टर और सेवानिवृत्त कर्मचारी क्वार्टर नियमों का आवंटन में१९ बार संशोधन हुए। निर्वासित तिब्बती संसद ने पहले ही १६वें कशाग द्वारा प्रस्तुत विधेयक को पारित कर दिया है, जिसका लक्ष्य तिब्बती प्रशासन के भीतर कार्यबल सीमांकन को मानकीकृत करना और

विशेष नियुक्तियों के लिए संरचित मानदंड और पूर्वापेक्षाएं स्थापित करना है। कशाग तिब्बती संसद के आगामी सत्र के दौरान एक नया विधेयक पेश करने की एक बार फिर तैयारी कर रहा है। इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य लोक सेवा आयोग के नियमों और विनियमों में अतिरिक्त संशोधन पेश करना है, जिसका लक्ष्य तिब्बती कार्यबल की समग्र संरचना को बढ़ाना और उनके विशेषाधिकारों और लाभों में एकरूपता को बढ़ावा देना है। इसी प्रकारचार्टर के संशोधनके अनुरूपहम वर्तमान में उन नियमों की गहन समीक्षा कर रहे हैं जो हमारी चुनावी प्रक्रियाओं की देखरेख करते हैं। संसद ने पहले ही हमारे प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य हमारे नवागत नौकरशाहों के लिए आवासीय क्वार्टरों का विस्तार करना है। इस विधेयक में कर्मचारियों के आवास के आवंटन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विरोधाभासी प्रावधानों से निपटने के प्रावधान भी शामिल हैं। तिब्बती बस्तियों की दीर्घकालिक स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए कशाग ने तिब्बतियों के बीच भूमि और आवास के आंतरिक हस्तांतरण को सक्षम करने के उपाय शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इसके अनुसारयदि वे हर दो साल की अवधि के भीतर कम से कम एक महीने के लिए अपनी बस्तियों के आवासों में निवास करते हैं तो उनके घर और भूमि के अधिकार बरकरार रहेंगे और उन्हें आवास छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।

हमारी कानूनी प्रणाली में एक और प्रगति यह हुई है कि चार्टर के अनुच्छेद-६७ में तिब्बती सर्वोच्च न्यायिक आयोग (टीएसजेसी) को अपनीप्रक्रिया,अपने नियम और कानून संहिता, न्यायपालिका संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य संहिता बनाने का अधिकार दिया गया है। इसटीएसजेसी का गठन १९९६ में किया गया।

चार्टर में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार हमारे चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के कामकाजको नियंत्रित करने वाले अतिरिक्त नियम विकसित किए गए थे। इसी प्रकारकशाग ने भी प्रशासनिक नियमों और विनियमों की एक शृंखला स्थापित की है। समय की बदलती जरूरतों के अनुरूप इन नियमों और विनियमों में लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। इसके अलावाचार्टर के अनुच्छेद-८२ में स्थानीय तिब्बती विधानसभाओं को स्थानीय गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले अपने स्वयं के नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार, सभी३९ स्थानीय तिब्बती विधानसभाओं ने अपने संबंधित नियम और कानून बनाए हैं।

इन नियमों और विनियमों ने प्रशासन और इसके वित्तीय प्रबंधन, गणमान्य व्यक्तियों और सिविल नौकरशाहों के अधिकारों के साथ ही जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत कानूनी आधार स्थापित किया है। इन विनियमों ने न केवल हमारे लोकतांत्रिक शासन के सभी पहलुओं की प्रभावशीलता को बढ़ाया है, बल्कि हमारे लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की भी रक्षा की है।

१९९२ में प्रवर्तित'इन द गाइडलाइंस फॉर फ़्यूचर तिब्बत्स पोलिटी एंड बेसिक फीचर्स ऑफ इट्स कांस्टीट्यूशन (तिब्बत की भावी राजनीति और उसके संविधान की बुनियादी विशेषताओं के लिए दिशानिर्देश)'में परम पावन दलाई लामा ने कहा है कि मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं तिब्बत की भविष्य की सरकार में कोई भूमिका नहीं निभाऊंगा। इसलिए सरकार में अकेले दलाई लामा की पारंपरिक राजनीतिक स्थिति के विकल्प की तलाश करें।' परिणामस्वरूप, २०११ में परम पावन ने अपने सभी राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार निर्वाचित नेतृत्व को सौंप दिए।

पिछले साल लोकतंत्र दिवस पर कशाग ने एक चार्टर समीक्षा समिति गठित करने की अपील की थी। इसके परिणामस्वरूप आखिरकार संसद नेचार्टर समीक्षा समिति गठित कर दी। नवगठित चार्टर समीक्षा समितिने अपना काम शुरू भी कर दिया है। हम, कशाग ने भी अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि समिति और संसद दोनों सीटीए के नौकरशाहोंसहित आम तिब्बती नागरिकों से बड़ी संख्या में प्राप्त अंतर्दृष्टि और राय पर उचित विचार करेंगे।

कशाग का मानना है कि कानून का शासन समता और न्याय की गारंटी की नींव पर खड़ा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का मूर्त रूप है। हममें से जो लोग, सर्वोच्या शक्ति जनता के हाथों में होने के लोकतांत्रिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं, उनके लिए राष्ट्र की प्रगति का पथ उसके नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। सीटीए के मौलिक उद्देश्यों और सार्वजनिक नीतियों को आकार देने और लागू करने में यही सिद्धांत काम करता है। भले ही हमने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, तिब्बत में स्वतंत्रता की हमारी आकांक्षा अभी भी अधूरी है। इसलिए, कशाग चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होने की हमारी अपील को दोहराना चाहेगा।

इस अवसर पर हम तिब्बत और उसके लोगों के उचित हित के निमित्त आपके अटूट समर्थन को लेकर आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सराहना व्यक्त करना चाहते हैं। हम अपने साथ आपकी निरंतर एकजुटता और मित्रता की आशा करते हैं।

अंत में, हम परम पावन महान चौदहवें दलाई लामा के दीर्घायुऔर परम पावन के प्रयासों के निरंतर फलने-फूलने और उनकी सभी महान आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।

◆ यूरोपीय संघ के सांसदों ने सीटीए की लोकतांत्रिक प्रणालीको समझने के लिए सिक्योंग पेन्पा छेरिंग से मुलाकात की

tibet.net, ३० सितंबर,२०२३

नई दिल्ली।३० सितंबर २०२३ कोऑस्ट्रिया और जर्मनी के सात सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय तिब्बत प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग से फ्रेडरिक नौमान फाउंडेशन फॉर फ्रीडम (एफएनएफ) के दक्षिण एशियाईक्षेत्रीय कार्यालय में मुलाकात की।इस कार्यक्रम का आयोजन एफएनएफ और सीटीए के संयुक्त तत्वा वधान में किया गया। एक उदारवादी फाउंडेशन के रूप में कार्यरत एफएनएफ आर्थिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, सुशासन और मुक्त बाजारों

की वकालत करता हैऔर १९९१ से सीटीए कास्थायी साझेदार बना हुआ है।

बैठक का प्राथमिक उद्देश्य सीटीए की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करना और निर्वासित तिब्बती सरकार की विकास-यात्राको समझना था। यह बैठक २९ सितंबर से ०८ अक्तूबर तक ईयूसांसदों के दक्षिण एशिया के शैक्षिक दौरे का हिस्सा थी। इस दौरे के दौरानसांसद दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रचलित लोकतांत्रिक प्रणालीकी जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से भारत और भूटान का दौरा करेंगे।

सिक्योंग के साथ बैठक के दौरान यूरोपीय सांसदों ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) को समझने, इसके कार्यों, शासन प्रक्रियाओं और सीटीए सांसदों के लिए चुनाव प्रक्रिया के बारे में गहराई से जानने में गहरी रुचि व्यक्त की। जवाब में, सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने सीटीए के मिशन और संचालन की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने सीटीए के भीतर लोकतांत्रिक ढांचे के महत्व पर जोर देते हुए निर्वासन में रहने वाले तिब्बतियों द्वारा सामना की जाने वाली दिन-प्रतिदिन की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। इसके अलावासिक्योंग छेरिंग ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिब्बती मुद्दे की वकालत करने में सिक्योंग कार्यालय द्वारा निभाई गई केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सीटीए और तिब्बती प्रवासियों को दिए गए अहम समर्थन के लिए यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल काआभार व्यक्त किया।यूरोपीय संघ का समर्थन तिब्बतियों के हितों को आगे बढ़ाने में यूरोप द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

यूरोपीय संघ प्रतिनिधिमंडल के भाग लेने वाले सदस्यों में ऑस्ट्रिया के सांसद यानिक शेट्टी, ऑस्ट्रिया की वियना लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य डोलोरेस बाकोस, जर्मनी के थुरिंगिया स्टेट पार्लियामेंट के ड्यूटी स्पीकर डिर्क बर्गनर, जर्मनी के जेना नगर निगम के विभागाध्यक्ष रेजिना बर्गनर, जर्मनी के एफडीपी बुंडेस्टाग समूह के संसदीय दल के नेता टॉर्स्टन हर्बस्ट, जर्मनी के संसद सदस्य सैंड्रा वीसर, क्रिस्टीन एशेनबर्ग-डुग्नसऔर ओलाफ इन डेर बीक शामिल थे।'

◆ चीन के 'ऑर्डर नंबर १९'से तिब्बत में उसका चल रहा निरंतर धार्मिक दमन और बढ़ा

tibet.net, ०१ सितंबर २०२३

धर्मशाला। निर्वासित तिब्बत सरकार के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) का सूचना एवंअंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर) उसनए चीनी विनियमन के बारे में चिंतित है जो ०१ सितंबर २०२३से लागू होने वाला है। इसके तहत तिब्बत के अंदर और चीन में अन्य जगहों पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बढ़ जाएगा। चीन के धार्मिक मामलों के प्रशासन ने 'मेजर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलिजिएस एक्टिविटी साइट्स (धार्मिक गतिविधि स्थलों के प्रशासन के लिए उपाय)'या 'ऑर्डर नंबर १९'की घोषणा की, जो कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) सरकार की धार्मिक स्वतंत्रता पर चल रही दमनात्मक कार्रवाई का एक और अगला कदम है।

पीआरसी सरकार के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट ने ३१ जुलाई २०२३ को अपनी वेबसाइट पर विनियमन की घोषणा की। इस विनियमन के लिए मंदिरों, मठों, मस्जिदों आदि को किसी भी धार्मिक गतिविधि आयोजित करने के लिए आधिकारिक अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जिसका लक्ष्य चीनी राष्ट्रवाद की मजबूत भावना को औरमजबूत करना और राष्ट्र निर्माण करना है। इसे चीनी भाषा और 'नस्लीयएकता'को बढ़ावा देने के साथ ही प्रचार और शिक्षा अभियानों के माध्यम से हासिल किया जाएगा।

इन जबरदस्ती के उपायों के साथ-साथ इसी तरह के कई 'आदेशों'का उद्देश्य तिब्बती बौद्ध सांस्कृतिक और राजनीतिक मामलों पर पीआरसी सरकार के नियंत्रण को अधिक कठोर करना है। विशेष रूप से, ऑर्डर नंबर १९के अनुच्छेद-२७में कहा गया है कि धार्मिक गतिविधि स्थलों के प्रबंधकीय संगठन के सदस्यों को 'चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व और शासन के वफादार समर्थक'और 'चीनी राष्ट्रीयता कामुख्य भूमि निवासी' होना चाहिए। इस गैरकानूनी विनियमन के तहत तिब्बत के वे तिब्बती मठ चीनी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का सामना करने के लिए विशेष रूप से असुरक्षित रहते हैं,जो पीआरसी द्वाराअलगाववादी माने गए परम पावन दलाई लामा की निंदा करने से इनकार करते हैं या उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा व्यक्त करते हैं।

तिब्बती बौद्ध धर्म का वैधानिकउत्पीड़न

बौद्ध धर्म चीन के आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त केवल पांच धर्मों में से एक हैऔर इसकी 'सामान्य धार्मिक गतिविधियां'१९८२ के चीनी संविधान के अनुच्छेद-३६के तहत नाममात्र संरक्षित हैं। फिर भीचीनी कम्युनिस्ट सरकार ने 'सामान्य' शब्द को बार-बारपरिभाषित किया है और उसकीगलत व्याख्या की है। ऐसा उसने सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के नाम पर संवैधानिक स्वतंत्रता पर लगाए गए और अधिक प्रतिबंधों को उचित ठहराने के लिए किया है। नया कानून धार्मिक स्थलों को ऐसी गतिविधियां करने से रोकता है जो 'राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती हैं,सामाजिक व्यवस्था को बाधित करती हैं और अन्य बातों के अलावाराष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाती हैं।'राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डालनेऔर सामाजिक व्यवस्था को बाधित करने की यह अस्पष्ट और व्यापक परिभाषा न केवल राजनीतिक गतिविधियों,मौलिक मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के उपयोग को अपराध ठहराती है। लेकिन जब भी चीनी सरकार जरूरत समझती है,यह कानूनतिब्बती बौद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियों कोभी अवैधानिक उत्पीड़न और दंड का शिकार बना लेता है।

१९९४ के बाद सेपीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) अधिकारियों ने तिब्बती बौद्ध मठों और भिक्षुणी विहारों में बड़े पैमाने पर कथित'देशभक्तिपूर्ण पुन: शिक्षा'अभियान चलाया है जो सरकार के प्रति

वफादारी और परम पावन दलाई लामा के प्रति किसी भी तरह के समर्थन और निष्ठा की निंदा करताहै। २०१० मेंपीआरसी सरकार ने 'ऑर्डर नंबर ८'पारित किया। इसे आधिकारिक तौर पर 'तिब्बती बौद्ध मठों के लिए प्रबंधन उपाय' के रूप में जाना जाता है।इसने तिब्बती बौद्ध मठों के आंतरिक मामलों पर सरकार के प्रबंधन और नियंत्रण को बढ़ा दिया। २००७ में 'ऑर्डर नंबर ५'या 'तिब्बती बौद्ध धर्म में जीवित लामाओं के पुनर्जन्म के लिए प्रबंधन उपाय' को अधिनियमित करकेचीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 'बौद्ध लामाओं के महत्वपूर्ण पुनर्जन्मों को चिह्नित करने की प्रक्रिया पर नियंत्रण' का दावा किया। इस ऑर्डर का मुख्य दीर्घकालिक ध्येय १५वें दलाई लामा को चुनने और मान्यता देने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना है।

ऑर्डर नंबर५ की घोषणा से पहले१९९५ मेंपरम पावन दलाई लामा द्वारा तिब्बत के सर्वोच्च लामाओं में से एक के अवतार के रूप में ११वें पंचेन लामा की मान्यता के बादचीन ने ११वें पंचेन लामाजेत्सुन तेनज़िन गेधुन येशी त्रिनले फुंटसोक पाल सांगपो को जबरन गायब कर दिया था। बौद्ध धर्म के११वें पंचेन लामा पिछले २८ वर्षों से गायब हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बार-बार प्रयास के बावजूद उनकी कुशलता और ठिकाने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

तिब्बती बौद्ध धर्म का चीनीकरण

पीआरसी सरकार केदशकों तक केअवैध कब्जे के बाद भी तिब्बत तेजकठोर धार्मिक नीतियों और कार्रवाइयों के तहतधार्मिक दमन से गुजर रहा है। शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद सेसीसीपी ने 'तिब्बती बौद्ध धर्म के चीनीकरण'की नीति को लागू करने को प्राथमिकता दी है। यह नीति धार्मिक समूहों को कम्युनिस्टपार्टी के शासन और विचारधारा का समर्थन करके पार्टी को धर्म से ऊपर माननेके लिए मजबूर करती है। चीनी अधिकारियों ने नियमित रूप से तिब्बतियों की धार्मिक स्थलों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है, धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है, धार्मिक स्थलों और प्रतीकों को नष्ट कर दिया है, तिब्बती भिक्षुओं और भिक्षुणियों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है, जेल में तिब्बती लामाओंपर अत्याचार किया है और परमपावन दलाई के सम्मान में आयोजितधार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वाले तिब्बतियों यालामाओं के पास परम पावन की तस्वीरें मिलने पर उन्हें हिरासत में लिया है। इसके अतिरिक्त०४ से १८ वर्ष की आयु के लगभग १०लाख तिब्बती बच्चों को वर्तमान में जबरन उनके माता-पिता से दूर चीनी औपनिवेशिक शैली के आवासीयस्कूलों में रखा गया है, जहां वे तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म केसीखने और बोलने के अवसर से वंचित हैं।

पीआरसी सरकार बार-बार परमपावन दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की नापाक कोशिशें करती है। वह यह दावा करती है कि परम पावन दलाई लामा के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का सर्वोच्चअधिकार उसके पास है। यह ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से असत्य हैऔर इस दावे को तिब्बती, अंतरराष्ट्रीय समुदाय,बौद्ध और बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा खारिज कर दिया गया है। परम पावन दलाई लामा ने २०११ के एक बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है,केवल उसी के पास इस बात का वैध अधिकार है कि वह कहांऔर कैसे पुनर्जन्म लेना चाहता है और उस पुनर्जन्मको कैसे मान्यता दी जानी है। इसलिए, परम पावन के पुनर्जन्म का अंतिम अधिकार परम पावन के पास ही सुरक्षित है, किसी अन्य सरकार या व्यक्ति के पास नहीं। पीआरसी सरकार ने लगातार तिब्बतियों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के वैध प्रयोग को प्रतिबंधित करने वाले नए-नए कानून और नियम बनाए हैं।इसके अलावा, इन नियमों का मुख्य उद्देश्य शी जिनपिंग के तिब्बती बौद्ध धर्म का'चीनीकरण'करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है।एक ऐसी प्रक्रिया है जो संभवतः समग्र रूप से तिब्बती पहचान को खत्म करके पूरा होनेवाली है।

तिब्बत में बिगड़ती स्थिति के मद्देनजरहम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वे तिब्बत में धार्मिक रीति-रिवाजोंऔर शिक्षाओं पर पीआरसी सरकार द्वारा लागू किए जा रहे गैरकानूनी और कड़े नियंत्रण के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके लिए वेसहयोगियों और साझेदारों की सामूहिक शक्ति और प्रभाव को मजबूत करें। क्योंकि चीन द्वारा केवल तिब्बत में अपना अधिकार बनाए रखने के लिए यह सब किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तिब्बतियों के धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए चीन पर इस बात के लिए दबाव डालना चाहिए कि वह अपनेअंतरराष्ट्रीय दायित्वों और अपने संविधान का सम्मान करे।भले ही वह कम्युनिस्ट पार्टी की वैधता और स्थिति में हस्तक्षेप करता हो या उसे चुनौती देता हो। जब तक पीआरसी सरकार अपनी भेदभावपूर्ण और प्रतिकूल तिब्बत नीतियों को पहचानने, स्वीकार करने और उनका समाधान करने में विफल रहती है, तब तक चीन-तिब्बत संबंधों में सुधार चुनौती बनी रहेगी। अंत मेंतिब्बती समुदाय की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिएयह जरूरी है कि पीआरसी सरकार बिना किसी पूर्व शर्त के परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ मध्यम-मार्ग नीति पर आधारित सार्थक बातचीत फिर से शुरू करे।

◆ तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कलास से मुलाकात की, ओजीपी ग्लोबल समिट २०२३ में भाग लिया

tibet.net, ०९ सितंबर २०२३

धर्मशाला। निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों-गेशे मोनलम थारचिन, लग्यारी नामग्याल डोलकर,छेनेछांग धोंडुप ताशी और फुरपा दोरजी ग्यालधोंग के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप (ओजीपी)ग्लोबल समिट-२०२३ में एस्टोनियाई प्रधानमंत्रीकाजा कलास और अन्य गणमान्य नेताओं से मुलाकात की। ०६ सितंबर, २०२३ को ओजीपी ग्लोबल समिट-२०२३ का मुख्य कार्यक्रम एस्टोनिया के तेलिन में टेलिस्कीवी लूमेलिनक हॉल में आयोजितहुआ। इस कार्यक्रम में एस्टोनिया के प्रधानमंत्रीकाजा कलास औरकोसोवो के प्रधानमंत्रीएल्बिन कुर्तीका संबोधन हुआ। इसके उपरांत

अमेरिकीविदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन,यूक्रेन के प्रधानमंत्रीडेनिस श्माइहाई,मलावी के राष्ट्रपतिलाज़रस चकवेराऔर डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपतिलुइस अबिनैडरका आभासी संबोधन हुआ। कार्यक्रमों की शृंखला में आगे तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया और चीनी कम्युनिस्ट सरकार के तहत तिब्बत के महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करने के लिए हर उपलब्ध अवसर का लाभ उठाया। कार्यक्रम से इतरसांसदों ने तिब्बत में चीन की दमनकारी नीतियों के तहत तिब्बती पहचान के विनाश, निर्वासितकेंद्रीय तिब्बती प्रशासनऔर अन्य के कामकाज, तिब्बती संसद के कामकाज पर दुनिया भर की सरकारों और आईएनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

ओजीपी शिखर सम्मेलन से इतर तिब्बती सांसदों ने ०७ सितंबर को २०२१कीनोबेल शांति पुरस्कार विजेता फिलिपिनो और अमेरिकी पत्रकार मारिया एंजेलिटा रेसा से मुलाकात की। नोबेल पुरस्कार विजेता ने याद कियाकि परम पावन दलाई लामा ने नोबेल पुरस्कार मिलने पर उन्हें कैसे बधाई दी थी और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए नोबेल समिति के फैसले और उनके काम की सराहना की थी।नोबेल पुरस्कार विजेता ने तिब्बती प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के लिए आभार व्यक्त किया और उनकी सराहना की।

तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के पूर्व प्रतिनिधि और तिब्बत समर्थक जैकी स्पीयर से भी मुलाकात की और तिब्बतियों के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अटूट समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। पूर्व प्रतिनिधि ने तिब्बती सांसदों के आग्रह परउन्हें निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया और उनसे मुलाकात की सराहना की।

प्रतिनिधिमंडल को उसी शाम कोएस्टोनिया के प्रधानमंत्रीकाजा कलास से मिलने और ओजीपी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री को अवगत कराने का अवसर मिला। उन्होंने प्रधानमंत्रीकोतिब्बत के अंदर की चिंताजनक स्थिति, बौद्ध धर्म और बॉन परंपराके चार संप्रदायों, तिब्बती पठार के पर्यावरणीय महत्व आदि का संक्षिप्त परिचय भी दिया। उन्होंने स्वतंत्र तिब्बत की तत्कालीन सरकार द्वारा वित्त मंत्री छेपोन वांगचुक डेडेन शाकाब्पा को जारी ऐतिहासिक शाकाब्पा पासपोर्ट और तिब्बत के मुद्दे से जुड़े अन्य टीपीआईई दस्तावेज़की एक प्रति भी भेंट की।

शिखर सम्मेलन के समापन के बादतिब्बती टीम ने यूएसएआईडी के प्रशासक और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत सामंथा पावर और ओजीपी के सीईओ संजय प्रधान से मुलाकात की। तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने ओजीपी की आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें तिब्बती औपचारिक स्कार्फ (कथा) भेंट किया।

शिखर सम्मेलन में तिब्बत, ताइवान और अन्य १०० देशों के प्रतिनिधियों सहित २००० प्रतिभागियों ने भाग लिया।

◆ स्वीडिश संसदीय शिष्टमंडल ने तिब्बतियों के साथ एकजुटता व्यक्त की

tibet.net, ०२ सितंबर २०२३

धर्मशाला।तिब्बती लोकतंत्र दिवस की ६३वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए धर्मशाला पहुंचेस्वीडिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल नेतिब्बती लोगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय मार्गरेटा एलिज़ाबेथ सीडरफेल्ट ने किया।

दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल में मॉडरेट पार्टी से माननीय सांसद मार्गरेटा एलिज़ाबेथ सीडरफेल्ट, जोहाना हॉर्नबर्गर, मैरी चार्लोट निकोलसन, मारिया विक्टोरिया स्टॉकहॉस, एलेक्जेंड्रा एंस्ट्रेल, एन-सोफी लिफवेनहेज, जॉन ई वेनरहॉल, स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी के सांसद माननीय रिचर्ड जोहान्स जोम्शॉफ़ और ब्योर्न सॉडर, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी से सांसद माननीय गुडरून मार्गरेटा ब्रुनेगार्ड, ग्रीन पार्टी से सांसद जैनीन सोफिया अल्म एरिक्सन और स्वीडिश तिब्बत समिति के माननीय कार्ल मैटियास और क्रिस्टीना इवा मारिया ब्योर्नरस्टेड शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल के साथ लंदन स्थित तिब्बत कार्यालयसे प्रतिनिधि सोनम छेरिंग फ्रासी और सचिव लोबसांग चोएडन सैमटेन भी थे।

डीआईआईआर सचिव कर्मा चोयिंग ने दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल केप्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की सराहना की और कहा कि इससे तिब्बतियों को बल मिलेगा कि दुनिया उन्हें भूली नहीं है।

प्रतिनिधिमंडल की नेता सांसद मार्गरेटा एलिज़ाबेथ सीडरफेल्ट ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में चार पार्टियों से ११ सांसद हैं। उन्होंने परम पावन दलाई लामा के साथ अपनी सकारात्मक मुलाकात के बारे में भी बताया और शांति को बढ़ावादेनेवाले उनके संदेश के महत्व पर जोर दिया।

निर्वासित तिब्बती लोकतंत्र की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इसने लिंग, आयु और अन्य सामाजिक वर्गीकरणों को समाहित करते हुए सभी को समान मतदान का अधिकार दिया और इसी तरह सभी को चुनाव में खड़े होने का समान अधिकार दिया है।

चीन द्वारा तिब्बत में चलाए जा रहे औपनिवेशिक आवासीय स्कूल प्रणाली की निंदा करते हुए उन्होंने चीन से आग्रह किया कि वह तिब्बतियों को अपने धर्म, संस्कृति, भाषा का पालन करने और अपनी तिब्बती पहचान को संरक्षित करने की स्वतंत्रता दे। उन्होंने कहा कि स्वीडिश तिब्बती संसदीय समर्थक समूह तिब्बत के मुद्दे को उठाने और विधेयक को लिखने में व्यस्त है।

इसके बाद सांसद ने स्थानीय प्रेस कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। स्वीडिश सरकार द्वारा तिब्बती लोगों के लिए कल्याण कार्यक्रम चलाए जाने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब मेंउन्होंने कहा कि हालांकि स्वीडिश सरकार अमेरिका की तरह राजनीतिक और वित्तीय सहायता नहीं दे सकती है, लेकिनवहअपने लोगों और तिब्बती समुदाय के साथ इस विषय पर चर्चा करके यह तय करने की कोशिश करेंगी कि इस तरह का कार्यक्रम चलाने में स्वीडेन कहां तक सक्षम हो सकता है।

तिब्बत के अंदर रहनेवालेतिब्बतियों के लिए संदेश देने के बारे में पूछे जाने परउन्होंने कहा कि सांसद समझते हैं कि तिब्बत में रहनेवालेतिब्बती दमनकारी परिस्थितियों में किस हद तक पीड़ित हैं लेकिन तिब्बती अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने तिब्बत के अंदर रहनेवाले तिब्बतियों के प्रति एकजुटता व्यक्त की।

◆ ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी ने तिब्बत में अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया

tibet.net, ०१ सितंबर २०२३

ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी (एएलपी) ने १७-१९ अगस्त को ब्रिस्बेन में आयोजित अपने ४९वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सर्वसम्मति से तिब्बत के अंदर अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया।

एएलपी के सांसद जूलियन हिल ने यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया है,'लेबर झिंझियांग और पूरे चीन में उग्युर और अन्य नस्लीयऔर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है। हम मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के निष्कर्षों से गंभीर रूप से चिंतित हैं कि यातना या दुर्व्यवहार के आरोप विश्वसनीय हैं।यौन और लिंग-आधारित हिंसा की घटनाओं के आरोप हैं और कुछ मानवता के विरुद्ध अपराध के उल्लंघन भीहो सकते हैं। लेबर पार्टी तिब्बत में शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण की रिपोर्टों से बहुत चिंतित है। हम सरकार द्वारा संचालित आवासीय स्कूलों में तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग करने, राजनीतिक विचारों की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए तिब्बतियों को हिरासत में लेने, तिब्बती धार्मिक अभिव्यक्ति के दमन, अत्यधिक सुरक्षा उपायों, बड़े पैमाने पर निगरानी, यात्रा पर प्रतिबंध और तिब्बती सांस्कृतिक अधिकारों और विरासत पर चीन की नीतियों जैसी परेशान करनेवाली रिपोर्टों पर भी नजर रखे हुए हैं। पूरे चीन में जबरन श्रम के इस्तेमाल को लेकर श्रमिक भी काफी चिंतित हैं। हांगकांग के अधिकारों, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के निरंतर क्षरण और लोकतंत्र समर्थक हस्तियों, विपक्षी समूहों को गिरफ्तार करने और उन पर दबाव बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के व्यापक दुरुपयोग से भी एएलपी बेहद चिंतित है।'

ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है। मई २०२२ सेयह सत्तारूढ पार्टी है और वर्तमान में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ इसके नेता हैं।

◆ ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर जेनेट राइस ने परमपावन दलाई लामा के पुनर्जन्म और तिब्बत में मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर चिंता जताई

tibet.net, ०५ सितंबर,२०२३

ऑस्ट्रेलिया। तिब्बती स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले ऑस्ट्रेलियाई सर्वदलीयसंसदीय समूह द्वारा सोमवार ०४ सितंबर को मनाए गए १२वें तिब्बत लॉबी दिवस के अवसर पर सीनेटर जेनेट राइस नेतिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति के साथ-साथ परमपावन दलाई लामा के पुनर्जन्म सेसंबंधित मुद्दे को लेकर चिंता जताई। जेनेट राइस लंबे समय से तिब्बत समर्थक और वकील हैं और तिब्बत के लिए ऑस्ट्रेलियाई सर्वदलीयसंसदीय समूह(एएपीपीजीटी) की सह-अध्यक्ष भी हैं।

सीनेट में एक प्रश्न-सत्र के दौरानसीनेटर राइस ने विदेश मंत्री पेनी वोंग से उन मानकोंके बारे में पूछा, जो वह चीनी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में वह अपनाना चाहती हैं ताकि चयन, शिक्षा और पारंपरिक धार्मिक रिवाजोंको सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि तिब्बती बौद्ध धार्मिक नेताओं की श्रद्धा तिब्बत में संरक्षित है और यह सुनिश्चित करना है कि अगले दलाई लामा के चयन में चीनी सरकार की कोई भूमिका न हो। विदेश मंत्री वोंग ने अपने जवाब में तिब्बत में अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण, विशेष रूप से औपनिवेशिक आवासीयस्कूलों में तिब्बती बच्चों को शामिल करने, राजनीतिक विचारों की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति परतिब्बतियों को हिरासत में लेने और तिब्बती धार्मिक अभिव्यक्ति के दमन पर चिंता व्यक्त की।

विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा,'हमने अपनी चिंताओं को अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के समक्ष उठाया हैऔर मैं कहूंगा कि यह पहली बार है कि किसी ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने मार्च में मानवाधिकार परिषद में हमारे राष्ट्रीय बयान में हमारी चिंताओं को उठाया थाऔर मैं फिर से कहता हूं कि इस तरह की कार्रवाई ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पहली बार की है।'

सीनेटर राइस द्वारा मंत्री वोंग से कियागया दूसरा प्रश्न तिब्बत में जबरन श्रम के बारे में था। उन्होंने पूछा कि क्या ऑस्ट्रेलिया जबरन श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। इस पर विदेश मंत्री वोंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने आधुनिक दासता अधिनियम के पैमाने पर इस पूरे प्रकरण की समीक्षा की है जिसके आधार पर सरकार अपनी कार्रवाई को अंतिम रूप देगी।

तिब्बत लॉबी दिवस ऑस्ट्रेलिया में तिब्बती समुदाय के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया-तिब्बत परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम है, जहां तिब्बती और तिब्बत समर्थक तिब्बत से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सांसदों से एक साथ मिलकर बातचीत करते हैं।

◆ डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग ने आईपीएसी के प्राग शिखर सम्मेलन में भाग लिया

tibet.net, ०६ सितंबर २०२३

प्राग। निर्वासित तिब्बती संसद की उिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग ने ०१और०२ सितंबर २०२३कोआयोजित चीन पर तीसरे अंतर-संसदीय गठबंधन (आईपीएसी) केप्राग शिखर सम्मेलन-२०२३ में भाग लिया। शिखर सम्मेलन का आयोजन

चेक गणराज्य केप्राग अवस्थितचेक चैंबर ऑफ डेप्युटीज और सीनेट के भवनों में की गई थी।इसमें ३० देशों के ५०जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान तीन नए देश-फिलीपींस, केन्या और पैराग्वे आईपीएसीनेटवर्क में शामिल हुए। तीनों देशों के जन प्रतिनिधि इसमें नामित किए गए।

०१ और ०२ सितंबर को३० देशों के ५०जन प्रतिनिधि प्राग में चेक चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ और सीनेट में एकत्र हुए और पिछले साल के निर्णयों पर काम करते हुए उपलब्धियों, चुनौतियों और सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने विस्तारवादी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियम-आधारित व्यवस्था, वैश्विक शांति,स्थिरता,स्वतंत्रता और लोकतंत्र के समक्षपेश की गई कई चुनौतियों के जवाब में लोकतांत्रिक रणनीतियों पर भी चर्चा की। शिखर सम्मेलन का फोकस चीन से संबंधित छह विषयों-ताइवान, नवीकरणीय निर्भरता, दूसरे देशों का दमन, हांगकांग, बेल्ट एंड रोड पहलऔर मानवाधिकार पर केंद्रित रहा।

तीसरे आईपीएसी वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी चेक गणराज्यकेआईपीएसी केसह-अध्यक्ष प्रतिनिधि ईवा डेक्रोइक्स और सीनेटर पावेल फिशर ने की। सभा का स्वागत चेक विदेश मंत्री जान लिपावस्की नेकिया। उन्होंने चेक गणराज्यके पहले राष्ट्रपति वैक्लाव हावेल और तिब्बती आध्यात्मिक नेता परमपावन दलाई लामा के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांटा गया था।

०२ सितंबर कोचेक गणराज्य के आईपीएसी सह-अध्यक्ष सीनेटर पावेल फिशर द्वारा प्राग आईपीएसी विज्ञप्ति कोऔपचारिक रूप से स्वीकार करने से पहलेजन प्रतिनिधियोंने हांगकांग लिबर्टी, विश्व उग्यूर कांग्रेस और निर्वासित तिब्बती संसद के प्रतिनिधियों को भी सुना। शिखर सम्मेलन के अंत में चीन गणराज्य के लेजिस्लेटिव युआन के अध्यक्षयू सी-कुन का आभासी संदेश प्रसारित किया गया।

निर्वासित तिब्बत संसद का प्रतिनिधित्व इसकी डिप्टी स्पीकर डोल्मा तेखांग नेकिया और तिब्बत के अंदर रहरहे तिब्बतियों द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने आग्रह किया कि दुनिया की कई सरकारों नेतिब्बत के इतिहास को समझे बिना पीआरसी की बातों पर भरोसा किया है और उसके आदेशों को स्वीकृती दी है। इस तरह की स्वीकृती से पीआरसी को अन्यत्र क्षेत्रीय दावों को दबाने मेंप्रोत्साहन मिलता है। असलियत यह है कि चीन ज्यादातर झूठे या भ्रामक ऐतिहासिक कथानकोंको प्रचारित करता है और तिब्बत पर अपने दावे को सही ठहराने के लिए ऐसे कथानकों का उपयोग करता है। इसलिएदुनिया को पता होना चाहिए कि पीआरसी आधुनिक दुनिया में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और तिब्बत एक ऐसा मुद्दा है, जिसे लेकर चीन को नियंत्रित किया जा सकता है। इस मुद्दे से बहुपक्षीय तरीके से निपटा जाना चाहिए। इसलिए, मैं आपसे आग्रह करती हूंतिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति को तिब्बत-चीन संघर्ष के संदर्भ में ही देखें और इसे अंतरराष्ट्रीय और अनसुलझे मुद्देके रूप में माना जाए।

उन्होंने आगे कहा कि यह नीला ग्रह हम मनुष्यो के लिए एकमात्र आवास है, इसीलिए इसे बचाए रखना हमारे अस्तित्व के लिए अहम है। इसीलिए, मानवता के सामने आने वाली ग्लोबल वार्मिंग जैसीपर्यावरणीय चुनौतियों की समग्र समझ के लिएविश्व नेतृत्व को तिब्बती पठार के वैश्विक महत्व को पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर तिब्बती पठार के प्रभाव और महत्वपूर्ण भूमिका दोनों को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू कराने की अपील की।

उन्होंने दोहराया कि चीन की पीआरसी सरकारके नेतृत्व को विश्व व्यवस्था में जिम्मेदार पक्षबनाना न केवल कम्युनिस्ट शासन के तहत पीड़ित समूहों के हित में है, बल्कि यह पीआरसी और चीनी लोगों के हित में भी है। उन्होंने सभी लोगोंसे इस दुनिया को शांति और सद्भाव से रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का आह्वान किया।

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी(सीसीपी) कुल मिलाकरतिब्बती सभ्यता का आधार औरहमारी पहचान के मूल सिद्धांतों-भाषा और धर्म को निशाना बना रही है। तिब्बत के सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित हस्तीको नियंत्रित करने का बीजिंग के प्रयास से यह साबित होता है कि सीसीपी के पास तिब्बत पर कानूनी, राजनीतिक और नैतिक रूप से शासन करने की कोई वैधता नहीं है। उन्होंने तिब्बत के लिए खड़े होने, सच्चाई के लिए खड़े होने और शांति और न्याय के प्रति विश्वास को जीवित रखने के लिए सभी तिब्बत समर्थक देशों की विधायिकाओं, उनकी सरकारों और वहां के लोगों को धन्यवाद देते हुए अपना संबोधन समाप्त किया।

शिखर सम्मेलन के दौरान डिप्टी स्पीकर तेखांग ने तीन चेक संसदीय तिब्बत हित समूहों के मुलाकात की। इनमें चेक संसदीय तिब्बत समूह के अध्यक्ष सीनेटर प्रेमिसल रबास,चैंबर ऑफ डेप्युटी के सदस्यहयातो जोसेफ ओकामुरा, चेक संसदीय तिब्बत समर्थक समूह के सचिव सीनेटर कतेरीना जैक्स शामिल थे। वह तिब्बत के एक कट्टर समर्थक श्री मार्टिन बर्सिक से भी मिलीं।उन्होंने उनदो तिब्बत समर्थक समूहों के साथ भी बैठकें कीं,जिनसे मिलने का प्रबंध एंड्रिया स्वोबोडोवा ने किया था। ये थे-लुंग्टा की निदेशक एडिटा क्लेकेरोवा और मोस्ट प्रोटिबेट गैब्रिएला गज़्डिकोवा। उन्होंने उन्हें तिब्बत में नई गतिविधियों से अवगत कराया और तिब्बत के प्रति उनके अटूट समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

उन्होंने तिब्बत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के लिए कार्यक्रमके आयोजकों और आईपीएसी कार्यकारी निकाय को धन्यवाद दिया। आईपीएसी सदस्यों और आईपीएसी कार्यकारी सदस्यों ने भी उनकी उपस्थिति की बहुत सराहना की। आईपीएसी शिखर सम्मेलन में सफल भागीदारी के बाद वह ०५सितंबर २०२३ को धर्मशाला लौट आईं।

◆ यूरोपीय बौद्ध संघ ने चीनी सरकार से तिब्बती बौद्ध मामलों में हस्तक्षेप न करने का आह्वान किया

tibet.net, २६ सितंबर २०२३

ब्रुसेल्स। यूरोपीय बौद्ध संघ (ईबीयू) ने २४ सितंबर २०२३ को अपनी वार्षिक आम बैठक के दौरान सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर चीनी सरकार से परम पावन दलाई लामा सहित तमामलामाओं के पुनर्जन्म को मान्यता देने सहित किसी भी तरह के तिब्बती बौद्ध मामलों में हस्तक्षेप न करने का आह्वान किया।

इसमें कहा गया है कि 'ईबीयू पुष्टि करता है कि परमपावन दलाई लामा सहित तिब्बती लामाओं के पुनर्जन्म का चयन करनातिब्बती लोगों और गैंडेन फोडरंग का विशेषाधिकार है, जिसे तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार किया जाना चाहिए। ईबीयू अंतरराष्ट्रीय समुदाय से चीनी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी भी लामा को मान्यता न देने का भी आग्रह करता है।'इसके अलावा, ईबीयू ने चीन सरकार से चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ फिर से वार्ताशुरू करने का आह्वान किया।

तिब्बती प्रतिनिधि रिगज़िन जेनखांग ने समय पर की गई पहल का स्वागत करते हुए इस मामले मेंपरम पावन के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए ईबीयू की सराहना की।

ईबीयू का यह आह्वान चीनी सरकार द्वारा हाल ही में 'धार्मिक गतिविधि स्थलों के लिए प्रशासनिक उपाय'की घोषणा के बाद आया है, जिसे 'आदेश संख्या १९'के तौर पर भी जाना जाता है। यह आदेश ०१ सितंबर २०२३ को लागू हुआ। माना जा रहा है कि यह कानूनतिब्बत और चीन में विभिन्न जगहों पर चल रहे धार्मिक दमन को और तेज कर देगा। यह उन उपायों की एक शृंखला में अगला कदम है,जिन्हें पीआरसी ने तिब्बती बौद्ध धर्म को निशाने पर लेते हुए अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिएपेश कियाऔर कार्यान्वित किया है।

ईबीयू यूरोप केबौद्ध संगठनों और राष्ट्रीय बौद्ध संघों का अंतरराष्ट्रीय छतरी संगठन है।

◆ सीजीटीसी-आई के प्रतिनिधिमंडल ने गंगटोक में ६३वें तिब्बती लोकतंत्र दिवस में भाग लिया, उत्तर बंगाल और सिक्किम का दौरा किया

tibet.net, ०३ सितंबर २०२३

सिक्किम। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया (सीजीटीसी-आई) के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर बंगाल और सिक्किम के दौरे के अंतिम चरण मेंतिब्बती लोकतंत्र दिवस समारोह की ६३वीं वर्षगांठ परसिक्किम की राजधानी गंगटोकमें एक कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल मेंसीजीटीसी-आई के राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार, क्षेत्रीय संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता, आईटीसीओ समन्वयक थुप्टेन रिनज़िन और उप समन्वयक तेनज़िन जॉर्डन ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल में सीजीटीसी-आई के क्षेत्रीय संयोजक श्री पेमा वांग्दा भूटिया भी शामिल थे, जो गंगटोक में हीरहतेहैं।

०२ सितंबर, २०२३ को गंगटोकमें आयोजित ६३वें तिब्बती लोकतंत्र दिवस समारोह में श्री सुरेंद्र कुमार और श्री सौम्यदीप दत्तासम्मानित अतिथि थे। गंगटोक स्थितितिब्बती सेटलमेंटकार्यालय और क्षेत्रीय डोमी एसोसिएशन द्वारा चोलखा सम हॉलमें आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विशिष्ट लोगों की उपस्थितिदेखी गई।

सिक्किम सरकार के धार्मिक मामलों, ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री सोनम लामा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथियों में विधायक श्री वाई.टी. लेप्चा, चिथ्यू यूडॉन औकात्सांगऔर अन्य शामिल हुए।

इस कार्यक्रम में तिब्बती और स्थानीय दोनों समुदायों की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही।इसमेंभारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) जैसे तिब्बत समर्थक समूह (टीएसजी) की उपस्थित उल्लेखनीय थी।

गंगटोक स्थित तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी लख्पा छेरिंग ने कशाग का वक्तव्य पढ़ा, जिसमें राज्य में तिब्बती समुदाय को लाभ पहुंचाने वाले हालिया सकारात्मक विकासों के बारे में जनता को जानकारी दी गई। चिथुए यूडॉन औकात्सांग ने निर्वासित तिब्बती संसद के बयान को पढ़ा, जिसमें विविध विचारों और दृष्टिकोणों का सम्मान करते हुए लोकतंत्र को संजोने के महत्व पर जोर दिया गया था।

आईटीसीओ समन्वयक थुप्टेन रिनज़िन ने स्थानीय समुदाय के बीच तिब्बत की वर्तमान स्थिति की जानकारी देकरजागरुकता बढ़ाने और उनका समर्थन हासिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने आईटीसीओ और सीजीटीसी-आई की पृष्ठभूमि की जानकारी देतेहुएदोनों का पूरापरिचय दिया।

श्री सौम्यदीप दत्ता ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच अंतर्संबंध की समझ को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया और तिब्बत में बड़े पैमाने पर चीन द्वारा बांध निर्माण के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर संभावित प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये राज्य पहले से ही चीनी नीतियों के परिणामों का सामना कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी मेंपरमाणु कचरे डालने से उत्पन्न प्रदूषण और तिब्बत में व्यापक खनन गतिविधियां

शामिल हैं।

विशिष्ट अतिथि श्री सुरेंद्र कुमार ने माननीय मंत्री सोनम लामा से सभी हिमालयी राज्यों के नेताओं की एक बैठक बुलाने का आग्रह किया, जिसमें केंद्र सरकार से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से निपटने के साथपरमपावन १४वें दलाई लामा को भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध करने का आग्रह किया जा सके। उन्होंने भारत के हितों की रक्षा के लिए तिब्बत के हितों को सबसे आगे रखते हुए भारत सरकार को अपनी तिब्बत नीति को फिर से व्याख्यायित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) द्वारादेश भर में अपने चैप्टर को ३०० तक विस्तारित करने की की योजना काभी खुलासा किया।

मुख्य अतिथि माननीय श्री सोनम लामा ने तिब्बत और भारत, विशेषकर भारत के हिमालयी राज्यों के बीच हजारों साल पुराने संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने परम पावन १४वें दलाई लामा के अविश्वसनीय योगदान की प्रशंसा की और उन उदाहरणों का वर्णन किया जब परम पावन ने सिक्किम को आशीर्वाद दिया था। उन्होंने श्री सुरेंद्र कुमार के सुझाव के प्रति समर्थन व्यक्त किया और सिक्किम के मुख्यमंत्री और अन्य हिमालयी राज्य के नेताओं के साथ मिलकर भारत सरकार से परमपावन को भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध करने का वचन दिया।

कार्यक्रममें तिब्बती मुद्दे के प्रति अटूट समर्थन के लिए श्री सुरेंद्र कुमार और श्री सौम्यदीप दत्ता का अभिनंदन भी किया गया। स्थानीय तिब्बती कलाकारों और गोर्शे छोकपा केसांस्कृतिक नृत्य मंडलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा दिए।

इस कार्यक्रम के साथ ही सीजीटीसी-आई के राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार, क्षेत्रीय संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता, आईटीसीओ समन्वयक थुप्टेन रिनज़िन और उप समन्वयक तेनज़िन जॉर्डन के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर बंगाल और सिक्किम के अपने सप्ताह भर के दौरे का समापन किया।इस दौरे का उद्देश्य तिब्बत समर्थक समूह (टीएसजी)को मजबूत और पुनर्जीवित करना औरसालुगाड़ा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और गंगटोक में तिब्बत जागरुकता को बढ़ावा देना था।

नई दिल्ली स्थित भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) ने तिब्बत मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए सप्ताह भर के दौरे का प्रबंध किया।

◆ ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत में '२१वीं सदी में तिब्बत को जानें' एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित

tibet.net, १४ सितंबर २०२३

नई दिल्ली। भारत- तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ), नई दिल्ली ने सेंटर फॉर नॉर्थ-ईस्ट एशियन स्टडीज, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स और ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत के सहयोग से १२ सितंबर २०२३ को तिब्बत पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का विषय था- '२१वीं सदी में तिब्बत को जानें (अंडरस्टैंडिंग तिब्बत इन द २१ सेंचुरी)'। सम्मेलन का आयोजन विश्वविद्यालय के ग्लोबल ऑडिटोरियम में किया गया।

दिन भर के सम्मेलन में कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भागीदारी की और अपने विचार रखे। इनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आनंद कुमार, तिब्बतविज्ञानी लेखक क्लाउडे अर्पि, ग्रेटर नोएडा स्थित शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हिमालयन स्टडीज के प्रतिष्ठित फेलो, तिब्बती कार्यकर्ता और लेखक तेनज़िन छुन्दुए, अंतरराष्ट्रीय तिब्बत नेटवर्क के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. लोबसांग यांग्त्सो और तिब्बत नीति संस्थान के रिसर्च फेलो धोंदुप वांग्मो शामिल रहे।

सम्मेलन की शुरुआत जेजीयू सोनीपत के जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. श्रीपर्णा पाठक और सहायक प्रोफेसर डॉ. मनोज पाणिग्रही के स्वागत भाषण के साथ हुई। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन प्रो. (डॉ.) श्रीराम चौलिया ने सम्मेलन के महत्व और २१वीं सदी में तिब्बत के महत्व पर प्रकाश डाला।

उनके बाद भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ), नई दिल्ली के समन्वयक थुप्टेन रिनज़िन ने अपने मुख्य भाषण में सम्मेलन के प्रतिष्ठित वक्ताओं का परिचय कराया और विशेष रूप से भारत के युवाओं के बीच तिब्बत की प्रासंगिकता को समझने के महत्व पर जोर दिया।

सम्मेलन के पहले सत्र का संचालन जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. स्वाति चावला ने किया। इस सत्र में डॉ. आनंद कुमार, क्लाउडे अर्पि और तेनज़िन छुन्दुए ने भारत-तिब्बत संबंधों के महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे।

डॉ. आनंद कुमार ने भारत के लिए तिब्बत के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि १९६२ के भारत-चीन युद्ध के बाद तिब्बत के प्रति उनका आकर्षण कैसे विकसित हुआ। उन्होंने बताया कि तिब्बत की उपेक्षा करना भारतीय नेताओं की ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि कई भारतीय इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनमें अक्सर अपने निकटतम

पड़ोसी तिब्बत के बारे में जागरूकता की कमी होती है। डॉ. कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि अब भारत के लिए तिब्बत के बारे में चर्चा में शामिल होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

क्लाउडे अर्पि ने भारत और तिब्बत के बीच सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों पर पावरपॉइंट के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। अपने व्याख्यान के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच प्राचीन काल से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों, भारत-तिब्बत सीमाओं, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे के बाद वहां हुए विकास और भारत पर पड़नेवाले इसके प्रभावों जैसे विषयों पर प्रकाश डाला।

तेनज़िन छुन्दुए ने अपनी प्रस्तुति में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी समुदायों के बीच सामान्य संस्कृतियों, भाषा और आध्यात्मिक परंपराओं का आदान-प्रदान करने वाले विशेष संबंध के साथ भारत-तिब्बत संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला।

सम्मेलन के दूसरे और दोपहर के सत्र का संचालन जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर डॉ. राजदीप पकानाटी द्वारा किया गया। इस सत्र में डॉ. लोबसांग यांग्त्सो और धोंडुप वांग्मोने तिब्बत के पर्यावरण और पारिस्थितिक पहलुओं पर अपनी बात रखी।

डॉ. लोबसांग यांग्त्सो ने 'तिब्बत की नदियां और भारत के लिए उनकी प्रासंगिकता' विषय पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने तिब्बत से निकलने वाली और भारत और पड़ोसी देशों में बहने वाली प्रमुख नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उनकी प्रस्तुति में चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत के भीतर इन नदियों के दोहन पर प्रकाश डाला गया, जो भारत और अन्य पड़ोसी देशों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

धोंदुप वांग्मो ने 'तिब्बत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और तिब्बती खानाबदोशों के पारिस्थितिकीय पुनर्वास' विषय पर अपनी प्रस्तुति दी। इसमें उन्होंने ग्लेशियरों के पिघलने, वनों की कटाई, खनन, बाढ़ और तिब्बती पठार को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य आपदाओं के साथ तिब्बत में हो रहे पारिस्थितिक विनाश पर प्रकाश डाला, जो कि तिब्बती पठार को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसका भारत और अन्य पड़ोसी देशों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

दोनों सत्रों के बाद सम्मेलन के वक्ताओं के साथ प्रश्नोत्तर का सत्र हुआ, जिसमें श्रोताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और सराहना की।

सराहना के प्रतीक के रूप में वक्ताओं को आयोजकों- सेंटर फॉर नॉर्थ-ईस्ट एशियन स्टडीज, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत और भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

सम्मेलन के समापन सत्र में आईटीसीओ नई दिल्ली के कार्यक्रम अधिकारी छोनी छेरिंग ने समापन भाषण दिया। विश्वविद्यालय के नार्थ-इस्ट एशियाई अध्ययन केंद्र के समन्वयक रक्षित शेट्टी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

सम्मेलन में धर्मशाला स्थित तिब्बत संग्रहालय को भी आमंत्रित किया गया था और उन्होंने परिसर में 'भारत-तिब्बत संबंध' शीर्षक से एक फोटो प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया, जिसमें छात्रों और संकायों की भीड़ उमड़ पड़ी।

भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली ने सम्मेलन के दौरान तिब्बत से संबंधित पुस्तकें भी वितरित कीं।

◆ 'विदेश नीति से परे तिब्बत' विषय पर सेमिनार में विशेषज्ञों ने तिब्बत की भयावह स्थिति पर प्रकाश डाला

tibet.net, १५ सितंबर, २०२३

नोएडा। भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ), नई दिल्ली और शिव नादर यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा के शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हिमालयन स्टडीज ने परिसर में १३ सितंबर २०२३ को संयुक्त रूप से 'विदेश नीति से परे तिब्बत (तिब्बत बियांड फॉरेन पॉलिसी)' विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में वक्ता के रूप में ग्रेटर नोएडा स्थित शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हिमालयन स्टडीज के प्रतिष्ठित फेलो, लेखक और तिब्बतविज्ञानी क्लॉउडे अर्पि और इंटरनेशनल तिब्बत नेटवर्क की वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. लोबसांग यांग्त्सो शामिल हुईं। सेमिनार की शुरुआत शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हिमालयन स्टडीज के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के निदेशक डॉ. जबिन टी. जैकब की परिचयात्मक टिप्पणियों के साथ हुई। डॉ. जैकब ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आज की दुनिया में तिब्बत का अपना महत्व है और दुनिया को इसे समझने के लिए तिब्बत को विदेश नीति से परे देखने की जरूरत है।

क्लॉउडे अर्पि ने 'तिब्बत अंडर चाइना: सेट अप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (चीन के अधीन तिब्बत: स्थापना और बुनियादी ढांचा)' शीर्षक से अपनी प्रस्तुति दी। अपने संबोधन में उन्होंने १९५९ में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे के बाद तिब्बत में नीतियों और विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने तस्वीरों का उपयोग करते हुए तिब्बत में चीन अपनाई जा रही नीतियों को सावधानीपूर्वक समझाया। तिब्बत में चीनी अधिकारियों का उद्देश्य तिब्बती संस्कृति को खत्म करना और तिब्बती रीति-रिवाजों को चीनी जीवन शैली में आत्मसात करने को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तिब्बत में बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की, जिससे

बहुसंख्यक हान चीनी बहुमत को फायदा होगा। जबकि तिब्बती पठार को मजबूत करने के चीन के प्रयासों से उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को रणनीतिक सैन्य लाभ भी मिलेगा। अर्पि की प्रस्तुति में सोशल मीडिया पर व्यापक निगरानी और चीनी अधिकारियों द्वारा दमनकारी निगरानी के साथ तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। हान चीनी निवासियों और लाखों हान पर्यटकों के तिब्बत में आगमन से तिब्बत की उभरती जनसांख्यिकीय संरचना ने तिब्बतियों को अपनी ही मातृभूमि में अल्पसंख्यक बना दिया है, जो तिब्बत के भीतर रहने वाली तिब्बती आबादी के लिए एक बेहद परेशान करने वाला मुद्दा है।

डॉ. लोबसांग यांग्त्सो ने 'तिब्बत्स रिवर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया (तिब्बत की नदियां और भारत के लिए इसका महत्व)' विषय पर एक प्रस्तुति दी। इसमें उन्होंने तिब्बत से निकलने वाली और भारत और निचले देशों में बहने वाली प्रमुख नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उनकी प्रस्तुति तिब्बत में इन नदियों के दोहन और चीनी अधिकारियों द्वारा व्यापक खनन गतिविधियों पर प्रकाश डालती है, जो भारत और पड़ोसी देशों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। डॉ. यांग्त्सो ने तिब्बत से निकलने वाली इन नदियों का भारत और अन्य पड़ोसी देशों के लिए महत्व पर प्रकाश डाला और तिब्बत की नदियों के पारिस्थितिकीय दोहन और विनाश से रक्षा के लिए सभी संबंधित देशों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा कीं।

शोध पत्र प्रस्तुति सत्र के बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हिमालयन स्टडीज में एसोसिएट फेलो डॉ. देवेन्द्र कुमार ने चर्चाकर्ताओं की टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। इनमें क्लाउडे अर्पि और डॉ. लोबसांग यांग्त्सो द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुरूप ही तिब्बत के अंदर की वर्तमान स्थिति, विशेष रूप से सीमा पर गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया था।
सत्र के बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ जहां वक्ताओं ने श्रोताओं, विशेषकर छात्रों के साथ विचारों का गहन आदान-प्रदान किया।
सेमिनार के अंत में आईटीसीओ नई दिल्ली के समन्वयक थुप्टेन रिनज़िन ने समापन भाषण दिया और ग्रेटर नोएडा स्थित शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हिमालयन स्टडीज के अमूल्य सहयोग के लिए सेंटर के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। सेंटर ने आयोजन की शानदार सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अतिथि वक्ताओं को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए धन्यवाद दिया। उनके शोध पत्रों में तिब्बत के विभिन्न आयामों और इसकी समकालीन प्रासंगिकता को स्पष्ट किया गया है।

श्री थुप्टेन ने इसके अलावा तिब्बती स्थिति को समझने और तिब्बती मुद्दे को समर्थन देने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने तीन प्रमुख पहलुओं पर जोर दिया- पहला भारत पर तिब्बत का ऐतिहासिक प्रभाव, दूसरा तिब्बत में चल रहे विकास का भारत पर प्रभाव और तीसरा तिब्बत से संबंधित मुद्दों का भविष्य में भारत पर अनुमानित प्रभाव।

सराहना के प्रतीक के रूप में भारत- तिब्बत समन्वय कार्यालय ने अतिथि वक्ताओं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हिमालयन स्टडीज, शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ग्रेटर नोएडा के सदस्यों को सम्मानित किया।

सम्मेलन में धर्मशाला से तिब्बत संग्रहालय को भी आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने परिसर में 'भारत-तिब्बत संबंध' शीर्षक से एक फोटो प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों और संकायों की भीड़ उमड़ पड़ी।

नई दिल्ली स्थित भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय ने सम्मेलन के दौरान तिब्बत से संबंधित पुस्तकें भी वितरित कीं।

◆ सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग ने कोलकाता के संस्कृत कॉलेज और विश्वविद्यालय में तिब्बत पर सेमिनार और यात्रा प्रदर्शनी आयोजित किया

tibet.net, १६ सितंबर, २०२३

कोलकाता। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर) के तिब्बत संग्रहालय के साथ संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क ने मिलकर भारत-तिब्बत संबंधों को लेकर पश्चिम बंगाल और सिक्किम के चार शहरों- कोलकाता, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और गंगटोक में प्रदर्शनी के साथ अपना ११ दिनों का भाषण दौरा शुरू किया। डेस्क के अधिकारी श्री तेनज़िन कुनखेन और सुश्री लोबसांग क्यिज़ोम ने तिब्बत में वर्तमान मानवाधिकार स्थिति और भारत और दुनिया के लिए तिब्बत के महत्व के बारे में बात की। सेमिनार में संस्कृत कॉलेज और विश्वविद्यालय के ४० से अधिक छात्रों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया।

सेमिनार के चार पैनलिस्टों में गणसम्मनय, कोलकाता की अध्यक्ष रूबी मुखर्जी, संस्कृत कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मौसमी सेन भट्टाचार्य और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तेनज़िन कुनखेन और लोबसांग क्यिज़ोम शामिल थे।

सेमिनार आयोजित करने में मदद करनेवाली कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज की पूर्व क्षेत्रीय संयोजक एडवोकेट रूबी मुखर्जी भी चार पैनलिस्टों में से एक थीं। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने उन संबंधों पर प्रकाश डाला जो ऐतिहासिक रूप से भारत और तिब्बत को एक साथ बांधते हैं और कहा कि तिब्बत के उचित कारण का समर्थन करना भारतीयों का नैतिक कर्तव्य है।

डीआईआईआर के मानवाधिकार डेस्क के कर्मचारी तेनज़िन कुनखेन ने

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का परिचय दिया और तिब्बत पर चीन के कब्जे की पृष्ठभूमि के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। उन्होंने आगे तिब्बत के अंदर विभिन्न तरह के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में बात की, जिसमें ड्रैकगो में चल रही कार्रवाई और विध्वंस, तिब्बत में चीनी औपनिवेशिक शैली के आवासीय स्कूल, 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' और तिब्बती बुद्धिजीवियों पर कार्रवाई शामिल है।

उन्होंने कहा, 'तिब्बत पर अपने कब्जे को वैध ठहराने और अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए चीनी सरकार तिब्बत में तिब्बतियों के मौलिक मानवाधिकारों की उपेक्षा करती है।'

डीआईआईआर की अनुसंधान और संचार अधिकारी लोबसांग क्यिज़ोम ने भारत के लिए तिब्बत के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने इस तथ्य को उजागर किया कि जब भारत की सुरक्षा चिंताओं की बात आती है तो तिब्बत को एक महत्वपूर्ण कारक क्यों माना जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भारत की तिब्बत नीति के पुनर्मूल्यांकन का आह्वान किया। उन्होंने कहा, 'अगर पीआरसी सरकार की मौजूदा नीतियों को चुनौती नहीं दी गई तो तिब्बत के साथ ही उसके पड़ोसी भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।'

सेमिनार से पहले तिब्बत संग्रहालय के कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय हॉल में प्रदर्शनी लगाई, जिसने इच्छुक छात्रों को आकर्षित किया। कर्मचारियों ने प्रदर्शनी के बारे में छात्रों के सवालों के जवाब दिए।

◆ मानवाधिकार डेस्क और तिब्बत संग्रहालय ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम के विश्वविद्यालयों में भाषण यात्रा और प्रदर्शनी पूरी की

tibet.net, २७ सितंबर, २०२३

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर) के तिब्बत संग्रहालय के साथ संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क ने तिब्बत संग्रहालय के साथ मिलकर पूरे पश्चिम बंगाल के कोलकाता, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गंगटोक शहरों के चार संस्थानों और एक स्कूल में अपना दो सप्ताह लंबा भाषण दौरा पूरा कर लिया है। भाषण दौरे के दौरान डीआईआईआर के कर्मचारी तेनज़िन कुनखेन और लोबसांग क्यिज़ोम ने तिब्बत में वर्तमान मानवाधिकार स्थिति पर चर्चा की और बताया कि चीन-तिब्बत संघर्ष का समाधान भारत और बाकी दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, दोनों वक्ताओं ने भारतीय कॉलेज के छात्रों से अपने लेखन और लेखों में तिब्बत में चीन के निराशाजनक मानवाधिकार रिकॉर्ड के खिलाफ आवाज उठाने और तिब्बत को जनता के ध्यान में सबसे आगे रखने के लिए उन्हें पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने का आग्रह किया। तिब्बत संग्रहालय की कर्मचारी तेनज़िन डोल्मा और तेनज़िन खेंटसे ने भारत और तिब्बत के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और दोनों देशों के बीच अतीत में और आज भी मौजूद मजबूत संबंधों के बारे में एक प्रदर्शनी प्रस्तुत की।

भाषण दौरे में चीनी कब्जे के तहत तिब्बत में विभिन्न मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया, जिसमें हाल के वर्षों में लारुंग गार और याचेन गार के विश्वविख्यात तिब्बती बौद्ध संस्थानों से वहां के निवासियों बेदखल करना और इन संस्थानों को ध्वस्त करना, खाम ड्रैकगो में धार्मिक मूर्तियों का विध्वंस, धार्मिक दमन, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन, यातना से होने वाली मौतें और तिब्बती लोगों का आत्मदाह शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने तिब्बत की धार्मिक रिवाजों, विशेष रूप से पुनर्जन्म प्रणाली में चीनी हस्तक्षेप के साथ ही केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण से संबंधित मामलों पर चर्चा की।

प्रस्तुति का दूसरा भाग मुख्य रूप से भारत के साथ-साथ पड़ोसी एशियाई देशों के लिए जल मीनार के रूप में तिब्बत के महत्व पर केंद्रित था। इसके अतिरिक्त वक्ता लोबसांग क्यिज़ोम ने तिब्बत के भारत के साथ दीर्घकालिक संबंधों पर चर्चा की। यह संबंध बौद्ध धर्म, चिकित्सा, भाषा और संस्कृति के संदर्भ में रहा है। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को विभिन्न माध्यमों से तिब्बती मुद्दे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे कि अपने इलाकों में तिब्बती समर्थक समूहों में भाग लेना, शोध पत्र लिखना और भारत और तिब्बत के बीच संबंधों और भारत और दुनिया के लिए तिब्बत के महत्व पर पूरा शोध प्रबंध लिखना आदि।

तिब्बत में मानवाधिकारों पर भाषण दौरे और भारत और तिब्बत संबंधों पर तिब्बत संग्रहालय में प्रदर्शनी के माध्यम से लगभग ४५० छात्र और संकाय सदस्य जुड़े। संस्कृत कॉलेज और कोलकाता विश्वविद्यालय, रायगंज विश्वविद्यालय, रायगंज, सेंट जोसेफ कॉलेज नॉर्थ पॉइंट, दार्जिलिंग और सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम के छात्र प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान वक्ताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़े। यह कार्यक्रम पहले से तय ४५ मिनट से अधिक समय तक चलता रहा।

१५ सितंबर, २०२३ की दोपहर को आईक्यूएसी विभाग, संस्कृत कॉलेज और विश्वविद्यालय, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के डीआईआईआर और गणसम्मनय, कोलकाता ने संयुक्त रूप से 'भारत और तिब्बत: इतिहास और विरासत' पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार के चार पैनलिस्टों में गणसम्मनय, कोलकाता की अध्यक्ष रूबी मुखर्जी, संस्कृत कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मौसमी सेन भट्टाचार्य, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की तेनज़िन कुनखेन और लोबसांग क्यिज़ोम शामिल हुईं। संस्कृत कॉलेज और विश्वविद्यालय में कुल ४० छात्रों और संकाय सदस्यों ने सेमिनार में भाग लिया।

डीआईआईआर टीम ने हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक स्कूल में भारत-तिब्बत संबंधों पर तिब्बत संग्रहालय प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसका श्रेय हिमालयन कमेटी फॉर एक्शन ऑन तिब्बत (हिमकैट)

के सचिव सोनम लुंडुप लामा को जाता है। प्रदर्शनी में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों सहित लगभग १०० लोगों ने भाग लिया। अपने अगले कार्यक्रम के लिए रायगंज रवाना होने से पहले डीआईआईआर टीम ने स्कूल में ही दोपहर का भोजन किया।

१९ सितंबर २०२३ की सुबह रायगंज विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने 'तिब्बत्स रेलिवेंस एंड व्हाई इट मैटर्स (तिब्बत की प्रासंगिकता और यह क्यों मायने रखता है)' विषय पर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। डीआईआईआर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में डीआईआईआर के वक्ताओं ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के बारे में संक्षेप में जानकारी दी और पीआरसी सरकार के तहत तिब्बत में वर्तमान मानवाधिकार स्थिति पर चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने तिब्बत को लेकर भारत सरकार की स्थिति पर चर्चा की और छात्रों और संकाय सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने सांसदों से भारत की तिब्बत नीति को संशोधित करने का आग्रह करें। प्रस्तुति के बाद छात्रों और संकाय सदस्यों ने सुझावों और प्रश्नों के माध्यम से तिब्बत के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया। रायगंज विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. दीपक कुमार रॉय और इतिहास विभाग के प्रमुख डॉ. बाबूलाल बाला, दोनों रायगंज विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करने के बेहद समर्थक थे। वार्ता में १०० से अधिक संकाय सदस्यों और छात्रों ने भाग लिया। बातचीत के बाद विश्वविद्यालय ने टीम के लिए दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया और उन्हें उनके अगले गंतव्य तक ले जाने के लिए एक वाहन की व्यवस्था की। कुलपति और विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने डीआईआईआर टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया।

डीआईआईआर टीम २० सितंबर २०२३ की दोपहर को दार्जिलिंग के सेंट जोसेफ कॉलेज नॉर्थ पॉइंट पहुंची। वहां उन्होंने चीनी शासन के तहत तिब्बत के अंदर बिगड़ती वर्तमान स्थिति के साथ-साथ समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधों को देखते हुए तिब्बत को गंभीरता से लेने वाले भारतीय युवाओं के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हजारों साल पुराना संबंध है। कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. समीर शर्मा द्वारा आयोजित वार्ता में विभिन्न सेमेस्टर के १०० से अधिक इतिहास के छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की आधिकारिक मध्यम मार्ग नीति से संबंधित प्रश्न पूछे। प्रस्तुति के बाद छात्रों को सेमिनार कक्ष के बाहर स्थित संग्रहालय प्रदर्शनी के बारे में पढ़ने का अवसर मिला।

२२ सितंबर २०२३ को डीआईआईआर टीम ने तिब्बत की मानवाधिकार स्थिति और भारत और अन्य एशियाई पड़ोसियों के लिए इसके महत्व के बारे में गंगटोक स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय में व्याख्यान के साथ अपने भाषण दौरे का समापन किया। प्रोफेसर डॉ. संगमू थेंडुप ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें इतिहास विभाग के छात्रों ने भाग लिया। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के कई वरिष्ठ बैच और संकाय सदस्यों ने भी बातचीत में भाग लिया, जिससे उपस्थित लोगों की संख्या १०० से अधिक हो गई। प्रस्तुति के बाद छात्रों और संकाय सदस्यों ने प्रश्न पूछे, जिनका वक्ताओं ने अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम उत्तर दिया। इतिहास विभाग की प्रमुख डॉ. अंबिका ढाका ने तिब्बत जागरुकता वार्ता आयोजित करने के लिए टीम की प्रशंसा करते हुए और विश्वविद्यालय और सीटीए के बीच भविष्य के सहयोग का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

भाषण यात्रा को कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। चर्चा में तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और तिब्बत पर अंतरराष्ट्रीय रुख के व्यवहार्य समाधान के रूप में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण और इस संघर्ष में छात्रों के योगदान को लेकर भी चर्चा हुई।

◆ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधिमंडल निर्वासित तिब्बती संसद पहुंचा

tibet.net, २४ सितंबर, २०२३

धर्मशाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तरी क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने २३ सितंबर २०२३ को निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया और डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग से मुलाकात की। डिप्टी स्पीकर ने बातचीत के दौरान आरएसएस प्रतिनिधियों को निर्वासन में तिब्बती लोकतंत्र के विकास, निर्वासित तिब्बती संसद की संरचना और कार्यप्रणाली और चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के सीटीए के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी।

डिप्टी स्पीकर ने लंबे समय से तिब्बत मुद्दे को समर्थन देने के लिए भारत और उसके लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रतिनिधियों से तिब्बत के संदेश को भारत में अपने-अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की अपील की। डिप्टी स्पीकर ने उन्हें निर्वासित तिब्बती संसद में महिला प्रतिनिधियों के आरक्षण, टीपीआईई की द्वि-वार्षिक संसद, निर्वासित तिब्बतियों के चार्टर को अपनाने और ग्रीनबुक के माध्यम से तिब्बती स्वैच्छिक योगदान के महत्व के बारे में भी जानकारी दी।

डिप्टी स्पीकर ने यह भी बताया कि तिब्बत भारत के लिए विशेष रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में क्यों मायने रखता है। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर में तिब्बती प्रवासियों की चुनाव प्रक्रिया, निर्वासित तिब्बती संसद के कामकाज, भारत भर में तिब्बती स्कूलों के बारे में प्रतिनिधिमंडल द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए।

इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधिमंडल को संसद भवन की एक-एक जानकारी देते हुए का भ्रमण भी कराया गया।

◆ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉरेस्पोंडेंट्स (आईएएफएसी) के प्रतिनिधिमंडल ने धर्मशाला में

tibet.net, २८ सितंबर, २०२३

धर्मशाला। नई दिल्ली स्थित भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) द्वारा आयोजित वार्षिक मीडिया आउटरीच कार्यक्रम में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स (आईएएफएसी) के चार सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने २४ सितंबर को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने २७ सितंबर को तिब्बती मुद्दे, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए), इसके संचालन और निर्वासित तिब्बती समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त की।

चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में स्ट्रैटन्यूज़ ग्लोबल के कूटनीतिक संपादक सूर्य गंगाधरन, द हिंदू में कूटनीतिक संपादक सुहासिनी हैदर, एबीपी लाइव में समाचार संपादक तथा कूटनीति और रक्षा मामलों की संपादक नयनिमा बसु और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई)/ यूनीवार्ता के विशेष संवाददाता सचिन बुधौलिया शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल के पहले दिन के कार्यक्रम में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) मुख्यालय और तिब्बत संग्रहालय का दौरा शामिल था, जहां उन्होंने संग्रहालय के कर्मचारियों की सहायता से तिब्बत से संबंधित प्रदर्शनियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

अगले दिन प्रतिनिधिमंडल ने परम पावन दलाई लामा से मुलाकात की और संक्षिप्त बातचीत की। इस मुलाकात में परम पावन ने नालंदा परंपरा के प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। परम पावन के साथ इस बातचीत को बाद में विभिन्न मीडिया चैनलों पर प्रसारित किया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने छुगलाखांग मंदिर परिसर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने गुरु बुमतसोक प्रार्थना सत्र का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राष्ट्रपति सिक्योंग पेन्पा छेरिंग से भी मुलाकात की। सिक्योंग ने प्रतिनिधिमंडल को सीटीए और तिब्बती आंदोलन के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जानकारी दी। सिक्योंग के व्यक्तिगत साक्षात्कार भी किए गए।

प्रतिनिधिमंडल अपनी यात्रा के दौरान तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय (एलटीडब्ल्यूए) में रुका, जहां उन्होंने पुस्तकालय के महासचिव न्गावांग येशी से मुलाकात की और पुस्तकालय के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने एलटीडब्ल्यूए के विभिन्न श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और बाद में तिब्बत से नए आए तिब्बतियों से मिलने के लिए तिब्बती स्वागत केंद्र पहुंचे।

दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बती चिकित्सा और ज्योतिष संस्थान, मेन-छे-खांग के मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने संस्थान के निदेशक थुप्टेन छेरिंग से मुलाकात की और संग्रहालय सहित संस्थान परिसर का दौरा किया। उन्हें संस्थान के डॉक्टरों से परामर्श करने का भी अवसर मिला।

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद (टीपीआइई) का दौरा किया और डिप्टी स्पीकर डोल्मा तेखांग से मुलाकात की। डिप्टी स्पीकर ने तिब्बत के अंदर तिब्बतियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतीपूर्ण स्थितियों से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि तिब्बत के अंदर रहनेवाले तिब्बती सांस्कृतिक संहार, मनमानी हिरासत, हिरासत में मौतों और अन्य अत्याचारों के बावजूद शांतिपूर्ण तरीकों से दमन का विरोध करना जारी रखे हुए हैं। डिप्टी स्पीकर के साथ अलग-अलग साक्षात्कार आयोजित किया गया और प्रतिनिधिमंडल ने उस स्थान का दौरा किया जहां संसद की कार्यवाही होती है।

प्रतिनिधिमंडल ने मैक्लोडगंज में तिब्बती युवा कांग्रेस (टीवाईसी), स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत-इंडिया (एसएफटी-इंडिया) और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ तिब्बत (एनडीपीटी) के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की।

अंत में, प्रतिनिधिमंडल ने अपर तिब्बती चिल्ड्रन विलेज (टीसीवी) का दौरा किया, जहां ग्राम निदेशक छुल्ट्रिम दोरजी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्कूल परिसर का दौरा किया, छात्रों से बातचीत की और छात्रों को प्रदान किए गए पोषण संबंधी वातावरण और समग्र शिक्षा से प्रभावित हुए।

इस यात्रा ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को एक अनूठा अनुभव प्रदान किया। यहां उन्हें तिब्बती समुदाय और उसके निर्वासित प्रशासन को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिला। इससे उनमें तिब्बती आंदोलन की गहरी समझ पैदा हुई और भारत में इसका समर्थन करने की प्रतिबद्धता नए सिरे से जगी।

मीडिया प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में सीटीए के डीआईआईआर द्वारा सचिव कर्मा चोयिंग, अतिरिक्त सचिव तेनज़िन लेक्षाय, ताशी फुंटसोक और नामग्याल छेवांग की उपस्थिति में रात्रिभोज का आयोजन किया गया। रात्रिभोज समारोह में सदस्यों का अभिनंदन किया गया।

चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली स्थित भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय के समन्वयक थुप्टेन रिनज़िन और कार्यक्रम अधिकारी छोनी छेरिंग भी थे।

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Thupten Rinzin
Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

थुप्तेन रिन्ज़ीन
समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पता: भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोन: 011–29830578
ई–मेल: coordinator@indiatibet.net

स्वीडिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बतियों के साथ एकजुटता व्यक्त की

एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कलास के साथ तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल।